जवाब दो!!!
सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2020/bbd/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 9 मई 2020

आखिर क्यों मचा हुआ है ग्रामीण विकास विभाग में बवाल?

ग्रामीण विकास विभाग में कंट्रोवर्सी

एसीएस राजेश्वर सिंह ने विशिष्ट सचिव आरुषी मलिक के पॉवर सीज किए

भास्कर न्यूज. जयपुर | राज्य में आईएएस अफसरों के बीच आपस में टकराव थम नहीं रहा। पिछले दिनों एक मीटिंग में एसीएस चिकित्सा रोहित सिंह व एसीएस गृह राजीव स्वरूप भिड़ गए थे। नया मामला ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के एसीएस राजेश्वर सिंह व विशिष्ट सचिव आरुषी मलिक के बीच के विवाद का है। 1989 बैच के आईएएस राजेश्वर सिंह ने मलिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पॉवर सीज करने के आदेश दिए हैं। मलिक के माध्यम से आने वाली सभी फाइलें अब एसीएस के पास सीधे भेजी जाएंगी। गुरुवार को जारी आदेश में राजेश्वर सिंह ने आरुषी मलिक पर उच्चाधिकारियों और अधीनस्थों से दुर्व्यवहार करने से लेकर विभागीय कामकाज नहीं करने जैसे आरोप लगाए है। अनापत्तियों का जवाब नहीं देने और कार्यालय व फोन पर उपलब्ध नहीं रहने के आरोप लगाते हुए सभी पावर सीज किए गए हैं। उनके पास जाने वाली फाइलों पर रोक लगाते हुए विभाग से जुड़ी तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठकों में उन्हें शामिल नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। तर्क दिया है कि सरकारी आदेशों में कहा कि समस्त पत्रावलियां उप सचिव से होते हुए सचिव के माध्यम से उन तक पहुंचने का प्रावधान है। चूंकि विभाग में सचिव नहीं है। ऐसे में कामचलाऊ व्यवस्था के तहत विशिष्ट सचिव के माध्यम से पत्रावलियां प्रस्तुत की जा रही हैं। ऐसे में उन्होंने पाया कि आरुषि मलिक का काम संतोषजनक नहीं है। योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग की स्थिति अत्यंत खराब है। इसका कारण ये भी है कि पत्रावलियां लंबे समय तक आरुषी के पास लंबित रहना, अनिर्णीत रहना, आपत्तियों का जवाब नहीं देना।

राजेश्वर सिंह

आरुषी मलिक

नरेगा के पदों में पदोन्नति की फाइल है विवाद की जड़

सूत्रों का कहना है कि विभाग के दोनों अफसरों के बीच विवाद चल रहा है। इसमें से एक विवाद का कारण नरेगा 700 कार्मिकों के पदों में पदोन्नति की फाइल भी है। इस फाइल पर वित्त विभाग की ओर से पूर्व में आपत्ति लगाई जा चुकी है। आरुषी मलिक ने यह फाइल वित्त विभाग के पास भेजी हुई है।

साभार:-दैनिक भास्कर,जयपुर संस्करण में दिनांक 08/05/2020 को प्रकाशित खबर

समाचार-विश्लेषण

विगत दो दिनों से राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में ग्रामीण विकास विभाग से जुडी एक प्रमुख खबर प्रकाशित हो रही है जिसमे विभाग के दो आईएएस अधिकारियों के बीच टकराव बताया जा रहा है|

यही नही, विवाद इतना बढ़ गया है कि विभाग के एसीएस राजेश्वर सिंह ने विभाग की विशिष्ट सचिव आरुषी मालिक के पावर सीज कर दिए है और राज्य के मुख्य सचिव को उनके विभाग से हटाने के लिए पत्र भी लिख दिया है|

एसीएस सिंह के अनुसार आरुषी मालिक का काम संतोषजनक नहीं है|उनकी वजह से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की योजनाओं की धरातल पर क्रियान्वयन और मोनिटरिंग ख़राब है|पत्रावलियां लंबित रखना,अनिर्णीत रखना और आपत्तियों का जवाब नहीं देना उनकी आदतों में शुमार है|

साभार:-दैनिक भास्कर,जयपुर संस्करण में दिनांक 09/05/2020 को प्रकाशित खबर

एसीएस व विशिष्ट सचिव के बीच विवाद गहराया

राजेश्वरसिंह ने सीएस को लिखा मलिक को मेरे विभाग से हटाएं

अब पदोन्नति की फाइल सिंह ने सीएस को भेजी

पॉलिटिकल रिपोर्टर . जयपुर | ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कामकाज को लेकर विशिष्ट सचिव आरूषी मलिक और एसीएस राजेश्वर सिंह के बीच विवाद और गहरा गया। इस मामले में एसीएस राजेश्वर सिंह ने शुक्रवार को सीएस डीबी गुप्ता को आरूषी मलिक के खिलाफ पत्र लिखकर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभाग से हटाने की मांग की। आरोप भी दोहराया कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है। दूसरी ओर इस विवाद की जड़ मानी जा रही पदोन्नति की फाइल को शुक्रवार को राजेश्वरसिंह ने सीएस को भेज दी। गौरतलब है कि राजेश्वरसिंह और मलिक के बीच बड़े विवाद की वजह 2012 से अटकी पदोन्नति की यही फाइल थी, जिसमें एसई, एक्सईएएन, एईएन का प्रमोशन अटका हुआ है। आज इस फाइल को सिंह ने एप्रूवल के लिए सीधे सीएस को भेज दिया। एसीएस कहते रहे हैं कि आरूषी फाइल को बेवजह अटका रही हैं।

राजेश्वर सिंह

आरुषी मलिक

विवाद की वजह- एईएन, एक्सईएन व एसई के प्रमोशन की फाइल

दरअसल आरूषी मलिक ने एईएन, एक्सईएन व एससी से जुड़े प्रमोशन आदि के मामलों में फाइल मार्क करके सीधे वित्त को भेज दी थी। यह फाइल एसीएस के माध्यम से जानी थी। वित्त से जब यह फाइल एसीएस सिंह के पास आपत्तियों के साथ लौटी तो सिंह को पता चला कि उनसे बिना पूछे ही नोटिंग के साथ फाइल मलिक द्वारा वित्त को भेजी गई थी। उधर आरूषी ने जो नोटिंग की थी, उससे एसीएस नाराज थे। हालांकि इस फाइल पर 2012 से ही कई आपत्तियां होती रही हैं। वित्त भी पूर्व में आपत्ति कर चुका है।

मानिटरिंग व एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी वापस ली : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कामकाज को लेकर एसीएस राजेश्वर सिंह ने बताया कि विशिष्ट सचिव से केवल योजनाओं और मॉनिटरिंग का प्रभार हटाया गया है। अधीक्षण अभियंता पंचायती राज और संयुक्त सचिव आयोजना ही मुझे रिपोर्ट करेंगे। बाकी सभी पांच आरएएस ज्वाइंट सेक्रेटरी पूर्ववत आरुषि को ही रिपोर्ट करते रहेंगे।

पॉवर पोलिटिक्स

ग्रामीण विकास विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है|जिसमे करोडो-अरबों का फंड आता है और कई महत्वपूर्ण योजनायें इस विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है ऐसे में एसीएस राजेश्वर सिंह द्वारा आरुषी मालिक की कार्यशैली पर सवाल उठा कर सीधे सरकार पर निशाना साधा है|गौरतलब है कि इस विभाग के मंत्री सचिन पायलट है और यह विवाद उनसे अछुता नहीं है|

साभार:-टाइम्सऑफ़ इंडिया,जयपुर संस्करण में दिनांक 09/05/2020 को प्रकाशित खबर

Top panchayati raj official's wings clipped

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: In a move that seeks to dilute certain administrative powers of panchayati raj department's special secretary Arushi Malik, additional chief secretary (ACS) rural development and panchayati raj department Rajeshwar Singh has issued an order stating that all files pertaining to monitoring and implementation of central and state government-run panchayati raj schemes must be sent directly to him and not through the special secretary.

The special secretary has also been asked not to hold any meeting or video conference or participate in any of the meetings/vc related to these schemes. The file pertaining to this has been sent to Chief Secretary D B Gupta, who will hear both the sides. It is likely that Malik could be transferred to some other department, said sources.

"At this point, since there is no secretary posted in the panchayati raj department, the files were routed through the special secretary and director of the department. However, the result of this has been completely unsatisfactory. Especially, implementation and monitoring of various central and state government-run schemes on the ground has been miserable," read the order issued by the ACS.

"Delay in clearing files pertaining to these schemes at the level of the special secretary, state of indecision on the files, not replying to the queries on these files, being unavailable on the phone and at office most of the times and misbehaving with senior officials and subordinates are the reasons for this," it added.

"In order to ensure smooth implementation of the schemes and to achieve the set target, it has been decided that all files pertaining to central and state government-run schemes like - FFC, SFC, construction of PRI Bhawan, Ambedkar bhawan and Kisan Seva Kendra, Janata Jal Yojana, Rajiv Gandhi Seva Kendra, gram panchayat development scheme, Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan, village master plan, decentralised participatory planning, Mukhya Mantri Grameen BPL Awas Yojana, Swamitva scheme and other central and state-run schemes - must be sent by the officer in charge directly to the ACS instead of sending it through the special secretary," the order added.

"This will ensure effective implementation of the schemes and so that the expected progress can be achieved. The special secretary shall neither hold any meeting or video conference related to the schemes, nor participate in any of the meetings/VC. Also, can't write letters related to the schemes," it further added.

According to sources in the department, delay in clearing the files pertaining to promotion of the engineers in the rural development and panchayati raj department was the tipping point in the case. In another order, joint secretary (II) and deputy commissioner Gaurav Chaturvedi has given all charges of engineers' establishment, which was earlier held by additional commissioner and joint secretary (III) Prem Singh Charan.

At this point, since there is no secretary posted in the panchayati raj department, the files were routed through the special secretary and director of the department. However, the result of this has been completely unsatisfactory. Especially, implementation and monitoring of various central and state government-run schemes on the ground has been miserable

RAJESHWAR SINGH
Addl chief secy | Rural development & panchayati raj department